

हरति ऊर्जा मुक्त पहुँच वनियिमों में संशोधन कयिा चर्चा में क्योँ?

हरयिाणा [वदियुत वनियिमक आयोग \(HERC\)](#) ने अपने [गरीन एनरजी](#) ओपन एक्सेस वनियिम, 2023 में संशोधन कयिा है।

मुख्य बदि

- खुली पहुँच के लयि वसितारति पात्रता:
 - 100 कलिवाट या उससे अधकि की अनुबंधति मांग वाले उपभोक्ता, चाहे एकल कनेक्शन के माध्यम से या वतिरण लाइसेंसधारी के एक ही वदियुत परचालन प्रभाग के अंतरगत 100 कलिवाट या उससे अधकि की कुल क्षमता वाले एकाधकि कनेक्शनों के माध्यम से, अब हरति ऊर्जा ओपन एक्सेस के लयि पात्र हैं।
- अपतटीय पवन परयोजनाओं के लयि अतरिकित अधभार छूट बढाई गई:
 - दसिंबर 2032 तक चालू की गई [अपतटीय पवन](#) परयोजनाओं से उत्पन्न बजिली और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बजिली को अतरिकित [अधभार](#) से छूट दी जाएगी। यह पछिली छूट को आगे बढाता है, जो केवल दसिंबर 2025 तक लागू थी।
- गैर-स्वतंत्र फीडर उपभोक्ताओं के लयि खुली पहुँच पर स्पष्टीकरण:
 - स्वतंत्र फीडरों से जुड़े नहीं रहने वाले पात्र उपभोक्ता ओपन एक्सेस का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे [ससिस्टम की बाध्यताओं](#) और अपने वतिरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाए गए कसिी भी [बजिली कटौती प्रतिबंध](#) को स्वीकार करें। ऐसे प्रतिबंधों के कारण कम नकिासी की भरपाई नहीं की जाएगी।

हरयिाणा वदियुत वनियिमक आयोग (HERC)

- इसकी स्थापना 17 अगस्त 1998 को हरयिाणा वदियुत सुधार अधनियिम, 1997 के प्रावधान के अनुसार एक स्वतंत्र [वैधानकि नकिाय](#) के रूप में की गई थी।
- हरयिाणा भारत का दूसरा राज्य था जसिने वदियुत क्षेत्र में सुधार एवं पुनर्रगठन की प्रक्रयिा शुरू की।
- हरयिाणा वदियुत सुधार अधनियिम, 1997 को हरयिाणा राज्य वधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारति कयिा गया था। 20 फरवरी 1998 को भारत के [राष्ट्रपति](#) की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, यह अधनियिम 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ।